भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

01.04.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 521 का उत्तर

रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय का आवंटन

***521. श्रीमती शांभवी:**
श्री अरुण भारती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पटरियों के नवीनीकरण, विद्युतीकरण और नई लाइनों के निर्माण के लिए निर्देशित इस आवंटन का पृथकतः विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित निधियों का राज्य-वार विशेषकर बिहार में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आर्थिक समीक्षा 2025-26 में रेलवे के परिचालन अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीतिक कदम उठाए गए हैं कि इस विशाल पूंजीगत परिव्यय के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को उनकी लागत में किसी वृद्धि के बिना समय पर पूरा किया जा सके?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 01.04.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 521 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार ने बजट अनुमान 2026-27 में 2,78,030 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से नए रेलपथ के निर्माण के लिए 79,072 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

भारतीय रेल द्वारा पिछले 11 वर्षों के दौरान रेल नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। भारतीय रेल में नए रेलपथ के निर्माण/कमीशनिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-25	34,428 कि.मी.	8.6 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग 6.75 लाख करोड़ रु. की लागत वाली 35,966 कि.मी. कुल लंबाई की 431 रेल अवसंरचना परियोजनाओं (154 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2025 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	154	16,142	3,036	1,45,318
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	22,753
दोहरीकरण/बहुपथन	244	15,644	6,736	1,22,858
कुल	431	35,966	12,769	2,90,929

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी, भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीवन संबंधी स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के परिणामस्वरूप, सभी क्षेत्रीय रेलों में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता मिली है।

बिहार

रेल बजट:

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,132 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2025-26	10,066 करोड़ रुपए (लगभग 9 गुना)

रेलपथ निर्माण:

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	318 कि.मी.	63.6 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	1,899 कि.मी.	172.6 कि.मी. प्रति वर्ष (2.5 गुना से अधिक)

स्वीकृत की गई परियोजनाएं:

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, बिहार में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 4,663 किलोमीटर लंबाई की 86,107 करोड़ रुपए लागत वाली 52 परियोजनाएं (31 नई लाइन, 01 आमान परिवर्तन और 20 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2025 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	31	2,691	516	16,814
आमान परिवर्तन	1	69	52	544
दोहरीकरण/बहुपथन	20	1,904	446	11,995
कुल	52	4,663	1,014	29,353

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	मुंगेर पुल (19 कि.मी.)	2,774
2	कोसी पुल (22 कि.मी.)	516
3	पटना पुल (40 कि.मी.)	3,555
4	हाजीपुर-बछवारा दोहरीकरण (72 कि.मी.)	930
5	किऊल-गया दोहरीकरण (123 कि.मी.)	1,200
6	कुरौता पतनेर-मनकठा-सतह त्रिकोण (8 कि.मी.)	129
7	रामपुरहाट-मंदारहिल नई लाइन और रामपुरहाट-मुराराई-तीसरी लाइन (160 कि.मी.)	1,500
8	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज और नरकटियागंज-भिखना ठोरी आमान परिवर्तन (295 कि.मी.)	1,193
9	सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली और सहरसा-फारबिसगंज आमान परिवर्तन (206 कि.मी.)	2,113
10	बख्तियारपुर फ्लाईओवर (4 कि.मी.)	402
11	कोसी नदी पर पुल सहित कटरिया-कुर्सेला कहीं-कहीं दोहरीकरण (7 कि.मी.)	222
12	अररिया-गलगलिया नई लाइन (111 कि.मी.)	4, 415

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा शुरू की गई कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	सीतामढ़ी-शिवहर नई लाइन (28 कि.मी.)	567
2	सकरी-हसनपुर नई लाइन (76 कि.मी.)	735
3	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान नई लाइन (42 कि.मी.)	1,511

4	नेओरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन (166 कि.मी.)	2,200
5	कोडरमा-तिलैया नई लाइन (65 कि.मी.)	1,626
6	हाजीपुर-सगौली नई लाइन (151 कि.मी.)	2,087
7	अररिया-सुपौल नई लाइन (96 कि.मी.)	1,605
8	गंगा नदी पर पुल सहित विक्रमशिला-कटरिया नई लाइन (26 कि.मी.)	2,090
9	हंसडीहा-गोड्डा नई लाइन (30 कि.मी.) को छोड़कर पीरपैंती-जसीडीह नई लाइन (97 कि.मी.)	2,140
10	सोननगर-पतरातू बहुपथन (291 कि.मी.)	5,148
11	समस्तीपुर-दरभंगा दोहरीकरण (38 कि.मी.)	624
12	रामपुर डुमरा-ताल-राजेंद्र पुल-अतिरिक्त पुल और दोहरीकरण (14 कि.मी.)	1,677
13	सगौली-वाल्मीकीनगर दोहरीकरण (110 कि.मी.)	1,280
14	मुजफ्फरपुर-सगौली दोहरीकरण (101 कि.मी.)	1,465
15	बरौनी-बछवारा तीसरी और चौथी लाइन (32 कि.मी.)	124
16	सोन नगर-अंडाल बहुपथन (749 कि.मी.)	12,334
17	बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया दोहरीकरण (104 कि.मी.)	2,192
18	बख्तियारपुर-फतुहा तीसरी और चौथी लाइन (24 कि.मी.)	931

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि।

रेलपथ नवीकरण:

2026-27 के लिए संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर कुल 1,20,389 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का अनुमान है, जिसमें से 46,189 करोड़ रुपए रेलपथ अवसंरचना की संरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं।

भारतीय रेल में रेलपथ अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और सुधार करना एक सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय रेल द्वारा रेलपथ के उन्नयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) पटरियां, लोचदार बंधन वाले अधिक चौड़ाई व भार वाले प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों (पीएससी), पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर एच-बीम स्लीपरों का उपयोग किया जाता है।
- टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग किया जा रहा है।
- ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 260 मीटर लंबाई वाले रेल पैनलों की आपूर्ति को बढ़ाया गयाहै, जिससे संरक्षा और यात्रा गुणवत्ता में सुधार होगा।
- पूर्ववर्ती पारंपरिक/बेहतर एसईजे के स्थान पर थिक वेब स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंटों का उपयोग किया जा रहा है।
- पटरियों के लिए बेहतर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग को अपनाना।
- रेलपथ की बेहतर अनुरक्षण क्षमता और विश्वसनीयता के लिए हाई आउटपुट प्लेन टैम्पर्स और प्वॉइंटों एवं क्रॉसिंग टैम्पर्स का उपयोग करके रेलपथ अनुरक्षण के लिए यंत्रीकृत प्रणाली को अपनाना।
- परिसंपत्ति विश्वसनीयता में और सुधार करने के लिए रेल ग्राइंडिंग मशीनों सहित अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग।
- पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।
- समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग।
- पटरियों और वेल्डों के परीक्षण के लिए उन्नत चरणबद्ध एरे प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- इष्टतम अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए संपूर्ण कार्यप्रणाली की जांच के लिए एकीकृत रेलपथ निगरानी प्रणाली (आईटीएमएस) और दोलन निगरानी प्रणाली (ओएमएस) की संस्थापना।
- यार्डों में रेलपथ मापदंडों की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए पोर्टेबल रेलपथ मापन ट्रॉली को अपनाना।

- **विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रेलपथ निरीक्षण रिकॉर्डों के एकीकरण और आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वेब सक्षम रेलपथ प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का उपयोग किया जा रहा है, ताकि उचित अनुरक्षण इनपुट प्राप्त हो सके।**

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, रेलपथ की गति क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 की तुलना में 2026 के दौरान रेलपथ की गति क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

खंडीय गति (कि.मी. प्रति घंटा)	2014		2026 (फरवरी, 2026 तक)	
	रेलपथ किलोमीटर	%	रेलपथ किलोमीटर	%
130 और अधिक	5,036	6.3	23,713	22.4
110-130	26,409	33.3	62,036	58.7
<110	47,897	60.4	19,923	18.9
कुल	79,342	100	1,05,672	100

रेल विद्युतीकरण:

रेल विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है तथा यह वर्ष 2004-14 में 5,545 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2014-24 में बढ़कर 53,122 करोड़ रुपए हो गया है।

- **भारतीय रेल में रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, लगभग 99.4% बड़ी लाइन नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष नेटवर्क में विद्युतीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2014-25 के दौरान और वर्ष 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

अवधि	मार्ग कि.मी.
2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

- **बिहार में, बड़ी लाइन नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/बहुपथन परियोजनाओं को विद्युतीकरण के साथ ही स्वीकृत और निर्मित किया जा रहा है।**

- **रेल विद्युतीकरण के लिए 2026-27 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।**

अमृत भारत स्टेशन:

रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में रेलवे स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैं:

- **रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार**
- **रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण**
- **स्टेशन भवन में सुधार**
- **प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार**
- **यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान**
- **लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ी/रैम्प का प्रावधान**
- **प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/सतह का निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर का प्रावधान**
- **'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान**
- **पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण**
- **दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ**
- **बेहतर यात्री सूचना प्रणाली**
- **प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान।**

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है। अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1,338 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 98 स्टेशन बिहार में स्थित हैं। बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
बिहार	98	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, अररिया कोर्ट, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बारसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहारशरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चकिया, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गावती, एकमा, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर जंक्शन, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करहागोला रोड, कटिहार जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लखमीनिया, लखीसराय जंक्शन, मधुबनी, महेशखुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मसरख, मोकामा, मोतीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जंक्शन, नबीनगर रोड, नरकटियागंज जंक्शन, नौगछिया, नवादा, पहाड़पुर, पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन, पीरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना), राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहेबपुर कमाल, सकरी, सलौना, सालमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जंक्शन, सुल्तानगंज, सुपौल, तारेगना, ठाकुरगंज, थावे

<u>स्टेशन जिनका कार्य पूरा किया जा चुका है</u>:

बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। बिहार में जिन स्टेशनों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
बिहार	05	पीरपैंती, सबौर, शिवनारायणपुर, सिमुलतला, थावे

अन्य स्टेशनों पर भी विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं और उपर्युक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार हैः

- बारसोई जंक्शन स्टेशन: पुराने क्वार्टरों को हटाने और उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र और 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- किशनगंज स्टेशन: प्लेटफॉर्म सं. 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म की सतह निर्माण, प्लेटफॉर्म सं. 1 और 2 पर पीने के पानी के नल, परिचलन क्षेत्र में सुधार, द्वितीय प्रवेश द्वार पर पार्किंग, पहुंच मार्ग और चारदीवारी के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बागवानी और 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- सालमारी स्टेशन: स्टेशन भवन के सुधार, प्लेटफार्म सं. 1 के विस्तार और उसकी ऊंचाई बढ़ाने तथा प्लेटफार्म सं. 1 पर प्लेटफार्म शेल्टर निर्माण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। परिचलन क्षेत्र और 3 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- ठाकुरगंज स्टेशन: प्लेटफॉर्म सं. 1 की ऊंचाई बढ़ाने, प्लेटफॉर्म सं. 2 पर प्लेटफॉर्म की सतह का निर्माण, प्लेटफॉर्म सं. 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। प्लेटफॉर्म सं. 1 पर प्लेटफॉर्म की सतह निर्माण, प्लेटफॉर्म सं. 2 पर शौचालय, कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

- इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को सापेक्ष प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार शुरू किया जाता है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/स्टेशन में संभाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर शुरू किए जाते हैं।
- भारतीय रेल में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक सुस्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जाँच तथा लेखापरीक्षण शामिल हैं। कार्य विभिन्न संहिताओं एवं नियमावलियों में निर्धारित मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप संपादित किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/पदाधिकारियों/बहुविभागीय दलों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण/लेखापरीक्षण/जाँचें की जाती हैं तथा क्षति सहित किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि पाई जाने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

- रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ व उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।
- सामान्यतः, अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाओं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। बिहार चार रेलवे जोनों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन जोनों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,828 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (जनवरी 2026 तक), ₹1,793 करोड़ का व्यय उपगत किया गया है।

परिचालनिक अनुपात:

2024-25 में रेलवे का परिचालनिक अनुपात 98.22% था। भारतीय रेल ने पेंशन व्यय सहित सभी राजस्व व्यय को पूरा करने के बाद, 2024-25 में 2,660 करोड़ रुपए का मामूली अधिशेष अर्जित किया।

*****